हरियाणा सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

CMGGA
Chief Minister's Good Governance Associates
for a progressive Haryana

व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन

संदेश

सुशासन वर्तमान शब्दावली लगता है, लेकिन यह तब से चला आ रहा है, जब से मानव समाज का विकास हुआ है। सुशासन के भाव से ही भारतीय संस्कृति में प्रजा के सुख में ही राजा का सुख माना गया है। सुशासन के कई पहलू हैं, जिनमें से प्रमुख हैं—जवाबदेही, पारदर्शिता, समावेशी विकास और जन भागीदारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 'सबका साथ–सबका विकास' का नारा सुशासन का ही मूलमंत्र है।

इसी मूलमंत्र को अपनाते हुए हमने व्यवस्था परिवर्तन और ईमानदार तंत्र द्वारा 21वीं शताब्दी का नया हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ वर्ष 2014 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी। इसके लिए पुराने–जर्जर सिस्टम को ठीक करना ही काफी नहीं था, बल्कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना जरूरी था। इसलिए अनेक ऐसी चीजें हुईं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं। हमने शुरू से ही भौतिक विकास के साथ–साथ जीवन के सभी मानदण्डों को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया। हम बड़े–बड़े भवन, पुल, सड़कें आदि बनाने तक ही विकास को सीमित नहीं मानते, इसलिए सर्विस डिलीवरी, समानता व अंत्योदय पर विशेष बल दिया गया। हमने सरकारी खजाने से निकले हर पैसे को समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए वह पैसा निकला है। पात्र परिवार को राशन, डी.बी.टी. द्वारा बैंक खातों में छात्रवृत्ति, पेंशन, किसान की पैदावार का पैसा, सबसिडी, मुआवजा आदि इसके उदाहरण हैं।

हमने ई–गवर्नेंस की सहायता से ऐसी नई व्यवस्थाएं बनाईं हैं, जिनसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। सी.एल.यू. का खेल खत्म हुआ, नौकरियों में पर्ची–खर्ची बंद हो गई। ऑनलाइन स्थानांतरण से तबादला उद्योग पर ताला लग गया।

मुझे सुशासन दिवस पर यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो नई व्यवस्था बनाई है, उससे किसी भी नागरिक को अपना हक लेने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। प्रदेश का कमजोर, गरीब व आम आदमी भी आज तरक्की की रफ्तार में शामिल होने का सपना देख सकता है।

इस समय जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें पूरा साल पिछली उपलब्धियों पर गर्व करने में ही नहीं बिताना है, बल्कि इसमें यह भी तय करना है कि अढ़ाई दशक बाद, जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो प्रदेश कैसा होगा। अपने सपनों का वह स्वर्णिम हरियाणा बनाने के लिए हमें निरंतर सुशासन पर अडिग रहना होगा। इसी संकल्प के साथ प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री

कैबिनेट मंत्री

श्री दुष्यंत चौटाला
उप मुख्यमंत्री

कमरा नं. 40/5, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740212

श्री अनिल विज
गृह मंत्री

कमरा नं. 32/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740793

श्री कंवर पाल
शिक्षा मंत्री

कमरा नं. 34/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740010

श्री मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री

कमरा नं. 49/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740157

श्री रंजीत सिंह
विद्युत मंत्री

कमरा नं. 39/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740231

श्री जय प्रकाश दलाल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

कमरा नं. 42/6, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2743709

श्री बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री

कमरा नं. 24/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740906

राज्य मंत्री

श्री ओम प्रकाश यादव
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 43–सी/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740867

श्रीमती कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 31/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740358

श्री अनूप धानक
पुरातत्व एवं संग्रहालय,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 47/8 सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740195

श्री संदीप सिंह
खेल एवं युवा मामले,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 30/9, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740892

अटल एक व्यक्ति नहीं...

विचार है

अटल एक जीवन नहीं...

संस्कार है

अनुक्रमांक

अनुक्रमांक

ऑटो अपील प्रणाली (ए.ए.एस.)	05
परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.)	07
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना	11
मेरी फसल–मेरा ब्यौरा	15
ऑनलाइन स्थानांतरण नीति	19
अंत्योदय सरल पोर्टल	21
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना	25
सुशासन से सेवा	27
हरियाणा की नई पहलें, जो केंद्र व दूसरे राज्य की सरकारों के लिए बनी प्रेरणा	29
हरियाणा को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान	30–35

का अधिकार अधिनियम 2014
AAS
Auto Appeal System
(आस)
(https://aas.saralharyana.nic.in)
का
लोकार्पण
श्री मनोहर लाल
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा
के कर-कमलों से
बुधवार, 1 सितंबर, 2021 को संपन्न हुआ
DITECH Haryana
Haryana Right To Service Commission
NIC Haryana State Center
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत
AAS
(आस)
का
लोकार्पण समारोह
सभागार, हरियाणा निवास, चंडीगढ़
बुधवार, 1 सितंबर, 2021
ANI

ऑटो अपील प्रणाली (ए.ए.एस.)

1. पहचान की गई समस्या

- लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2014 में लागू किया गया था।
- जटिल प्रक्रिया–अपील दायर करने में असुविधा।
- समय पर सेवाएं देने में अप्रभावी।
- अगस्त 2021 तक 7 सालों में केवल 7 अपील दायर।
- अपीलीय प्राधिकारी को पहले मैनुअल अपील दायर होती थी।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार

- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2015 के नियम–3 में संशोधन।
- हरियाणा सेवा का अधिकार नियमों में ऑटो अपील का प्रावधान करने के लिए संशोधन किया।
- ऑटो अपील प्रणाली को अंत्योदय सरल प्लेटफार्म से जोड़ा।
- इस पोर्टल पर उपलब्ध 570 योजनाएं व सेवाएं AAS से जुड़ गईं।
- अब समय पर सेवा नहीं मिलती है तो आवेदन स्वतः अपीलेट अथॉरिटी में चला जाता है।
- सेवाओं और समय सीमा के लिए विभागों को अधिसूचना जारी।
- सेवाओं की डिलीवरी की निरंतर निगरानी।

3. लाभ

- सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता– इस सॉफ्टवेयर में हर कोई देख सकता है कि कितने मामलों में देरी हुई है और कौन अधिकारी जिम्मेदार है।
- आवेदकों की ईज़ ऑफ लिविंग– इस सिस्टम से आवेदक का जीवन सुगम हुआ और उसे अपील की स्थिति के बारे ई–मेल और एस.एम.एस. से सूचना।
- संतुष्टि सूचकांक– आवेदक सेवाओं की डिलीवरी के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर हैप्पीनेस रेटिंग फीचर के तहत रेटिंग दे सकते हैं।
- कागज आधारित फाइलों में भारी कमी–यह कागज रहित फाइलिंग सुनिश्चित करता है।
- लाल फीताशाही पर रोक–अधिसूचित समय सीमा समाप्त होने पर, आवेदक का आवेदन स्वतः ही प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी, फिर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी और फिर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को अग्रेषित हो जाता है।

4. परिणाम

- अगस्त 2021 तक 7 सालों में केवल 7 अपील दायर।
- AAS के अंतर्गत 5 सितम्बर, 2021 से 9 दिसम्बर, 2021 तक कुल 14,902 अपील दायर।

मेरा परिवार-समृद्ध परिवार
हर परिवार की पहचान
परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह
दिनांक : 4 अगस्त,2020
स्थान : पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर, ऑडिटोरियम, पंचकूला
मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
दुष्यंत चौटाला
परिवार पहचान पत्र

परिवार पहचान–पत्र (पी.पी.पी.)

1. पहचान की गई समस्या

- हर सरकारी एजेंसी अपना स्वयं का डेटा रखती है और उसी के अनुसार योजनाओं व सेवाओं का लाभ देती है।
- आमतौर पर इस डेटा को अपडेट नहीं किया जाता और योजनाएं पुराने डेटा के आधार पर ही लागू की जाती हैं।
- इससे पात्र गरीब परिवार अक्सर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं और अपात्र लाभ उठा जाते हैं।
- किसी भी सरकारी सेवा या योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को पहचान, जाति के प्रमाण, आय के प्रमाण, जन्मतिथि के प्रमाण आदि के रूप में कई दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं।
- 'आधार' व्यक्ति आधारित है, जबकि योजनाएँ परिवार को इकाई मानकर आधारित की जाती हैं।
- नागरिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील, जो अपडेट नहीं होती, इससे अपात्र लोग लाभ उठाते हैं।
- लाभ हेतु नागरिकों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बार–बार सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार

- पी.पी.पी. के क्रियान्वयन के लिए नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग की स्थापना।
- सितंबर 2021 में हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 को अधिनियमित और अधिसूचित किया तथा परिवार पहचान–पत्र अथॉरिटी का गठन किया।
- परिवार आधारित आई.डी. यानी परिवार पहचान–पत्र बनाना।
- इसमें परिवार के सभी सदस्यों, उनकी आय, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता आदि के विवरण सहित सामाजिक–आर्थिक आंकड़ा उपलब्ध।
- औद्योगिक संगठित श्रमिक के व्यवसाय और आय की जांच के लिए श्रमिक डेटा, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशनभोगियों, किसानों का डेटा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सेवा के माध्यम से आयकर डेटा, पंजीकृत सन्निर्माण श्रमिक डेटा, स्कूलों और कॉलेजों का विद्यार्थी डेटा आदि को आपस में जोड़ना।
- पी.पी.पी. में प्रतिदिन डेटा अपडेट करने के लिए जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के डेटा को जोड़ना।
- जाति वर्ग का एकबारगी सत्यापन किया, जिसमें आरक्षित जातियों के 85 प्रतिशत से अधिक परिवार सत्यापित।
- सरकारी कर्मचारियों के साथ–साथ स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय समितियों के माध्यम से सत्यापित नागरिकों का आय डेटा।
- सरकारी एजेंसियां लाभ देने के लिए परिवार के सामाजिक– आर्थिक विवरण सम्बन्धी आंकड़ा सिंगल पी.पी.पी. आई.डी. से प्राप्त कर सकती हैं।
- यह डेटा सब योजनाओं में काम आएगा और हर योजना के लिए अलग से आंकड़ा नहीं जुटाना होगा।
- कई स्रोतों से उपलब्ध डिजिटल डेटा के आधार पर मासिक स्तर पर बी.पी.एल. डेटा में संशोधन।
- नागरिकों को सेवाओं, योजनाओं का लाभ बिना आवेदन के घर बैठे ही।
- पी.पी.पी. आई.डी. के कार्यान्वयन के लिए 45 से अधिक विभागों को अधिसूचना।

परिवार समृद्धि
Haryana E-Parivar Pehchan Patra
H.O.F. : Desh Raj
MOTHER NAME : Santra Devi
D.O.B.: 01/01/1974
FATHER NAME : Bachan singh
SPOUSE NAME : Sobha Devi
MOBILE NO.: 741xxxx778
Haryana e-Parivar Pehchan Patra
हरियाणा ई-परिवार पहचान पत्र

- जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र और आय प्रमाण–पत्र स्वचालित ढंग से जारी।
- केंद्रीय डेटाबेस में सत्यापित और अपडेटेड पात्रता डेटा की आसान उपलब्धता।
- योजना के लाभार्थियों के चयन को सरल बनाया, जिससे दक्षता बढ़ी।

3. लाभ

- पी.पी.पी. से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में लीकेज की आशंका कम और लाभ सीधे लाभार्थी तक।
- सबसे गरीब व्यक्ति को सबसे पहले लाभ।
- केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही लाभ मिलेगा।
- सभी योजनाओं और सेवाओं को केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ने से शासन सुधार होगा और सरकारी सेवाओं के सक्रिय वितरण के साथ सावधि आधार पर नागरिकों का सामाजिक–आर्थिक विवरण अपडेटेड होगा।
- बी.पी.एल. सूची का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन शुरू और नई बी.पी.एल. सूची तैयार की जा रही है।
- वर्ष 2021 में सभी कॉलेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में दाखिलों को जाति व आय के स्वतः सत्यापन के साथ पी.पी.पी. से जोड़ा।

4. परिणाम

- पी.पी.पी. से 450 से अधिक सेवाएं जोड़ीं।
- 65 लाख से अधिक परिवारों के 2.57 करोड़ से अधिक सदस्य पी.पी.पी. के साथ पंजीकृत।
- हरियाणा के 90 प्रतिशत परिवारों के पास पी.पी.पी. आई.डी.।
- न्यूनतम आय वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू।
- गलत तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले 1 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की पहचान की।
- निर्धारित आय–सीमा से कम आय और 2022 में 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की सक्रिय पहचान की प्रक्रिया जनवरी 2022 में शुरू होगी, ताकि आवेदन किए बिना ही लाभार्थी को भत्ता प्रदान किया जा सके।
- कोविड–19 महामारी में 590.93 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता जरूरतमंदों के खातों में सीधी डाली गई।

लाभार्थी

मैं आटा चक्की का कारोबार संभालता हूँ। डेंगू बुखार के कारण मैंने चलने की क्षमता खो दी है। परिवार पहचान पत्र के तहत हमें योजनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हुई और अब मैं आय बढ़ाने के लिए आटा चक्की के कारोबार का विस्तार करना चाहता हूँ, और इसके लिए PMEGP के तहत 3 लाख का लोन स्वीकृत हो गया है। हम परिवार पहचान पत्र से बहुत खुश है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा के गरीब परिवारों को योजनाओं तक पहुंचाने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता कर रहा है।

(तारा चंद, ढांड, कैथल)

आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
जिला पंचकूला

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

1. पहचान की गई समस्या

- सबसे गरीब व्यक्ति को लाभ न पहुंचना।
- सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अति गरीब व्यक्ति आमतौर पर छूट जाता है।
- प्रत्येक सरकारी एजेंसी/विभाग स्वतंत्र रूप से अपनी योजना लागू करते हैं।
- अति गरीब व्यक्ति की जरूरत और क्षमता का समय–समय पर मूल्यांकन न होना।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार

- अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1.80 लाख रुपये करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।
- ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की गई, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम थी।
- प्रत्येक परिवार का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन जैसे उपायों का एक पैकेज अपनाया और तैयार किया जा रहा है।
- कई सम्बंधित योजनाओं के लाभ प्रदान करने में बैंकों को भी शामिल किया गया है।
- चिन्हित अंत्योदय परिवारों को आमंत्रित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें सभी संबंधित सरकारी एजेंसियां और बैंक मौजूद रहे।
- बैंकों द्वारा आवेदनों का मौके पर ही मूल्यांकन किया गया।
- निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की गई और सहायता के लिए योजना की पहचान की गई।
- राज्य को 274 जोन में बांटा गया।
- परिवारों के आकलन के लिए विभिन्न विभागों के सदस्यों की जोनल कमेटियों का गठन किया गया।
- सदस्यों द्वारा प्रत्येक परिवार का विशिष्ट आवश्यकता मूल्यांकन किया गया।
- चिन्हित योजना की प्रक्रिया हेतु सभी जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष मौके पर उपस्थित रहे।

3. लाभ

- परिवार आत्मनिर्भर होगा।
- सरकार की रोजगार योजनाओं से पात्र परिवारों को जोड़ना।
- शुरुआत में मौजूदा योजनाओं का लाभ प्रदान करने या आवेदक की शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के अनुसार ऋण को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

4. परिणाम

- राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार, रोजगार, कौशल विकास आदि से संबंधित पहले से ही चल रही 18 विभागों की 54 योजनाओं की पहचान की गई।
- मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है।
- योजना के तहत सहायता के लिए 1,48,333 परिवारों की पहचान की गई।
- इस योजना को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए 160 जगहों पर 292 अंत्योदय उत्थान मेले आयोजित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री अंत्योदय
परिवार उत्थान
योजना मेला
मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार
माननीय श्री अनिल विज जी
गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार

लाभार्थी

मैं मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता हूँ। पहले मैं जिस दुकान में काम करता था, वह मेरे घर से 2–3 किलोमीटर की दूरी पर थी। और पूरी तरह से दिव्यांग होने के कारण रोजाना इतनी दूरी तय करना मेरे लिए मुश्किल काम था। दिव्यांगजनों के लिए सेवा और व्यापार क्षेत्र योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई और साथ ही उसे संवितरित किया गया। अब मैंने दुकान पर दूर जाने के बजाय अपने आवास के पास मिट्टी के बर्तन का काम शुरू कर दिया है। मैं अब लगभग 15,000 से 18,000 रुपये प्रति माह कमा लेता हूँ। मैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार का आभारी हूँ।

(राम निवास, बेगु रोड, सिरसा)

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं का सक्रिय वितरण किया जा रहा है। मैं अपने 7 परिजनों का पालन–पोषण कर रही हूँ तथा अपने कार्य को विस्तारित करके अपनी आय बढ़ाना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से PMEGP के तहत मेरा लोन स्वीकृत किया गया है अब मैं सिलाई का काम सीखकर अपना कारोबार शुरू करूंगी ताकि स्वावलम्बित हो सकूं और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकूं।

(रितु गर्ग, गांव गोंदर, करनाल)

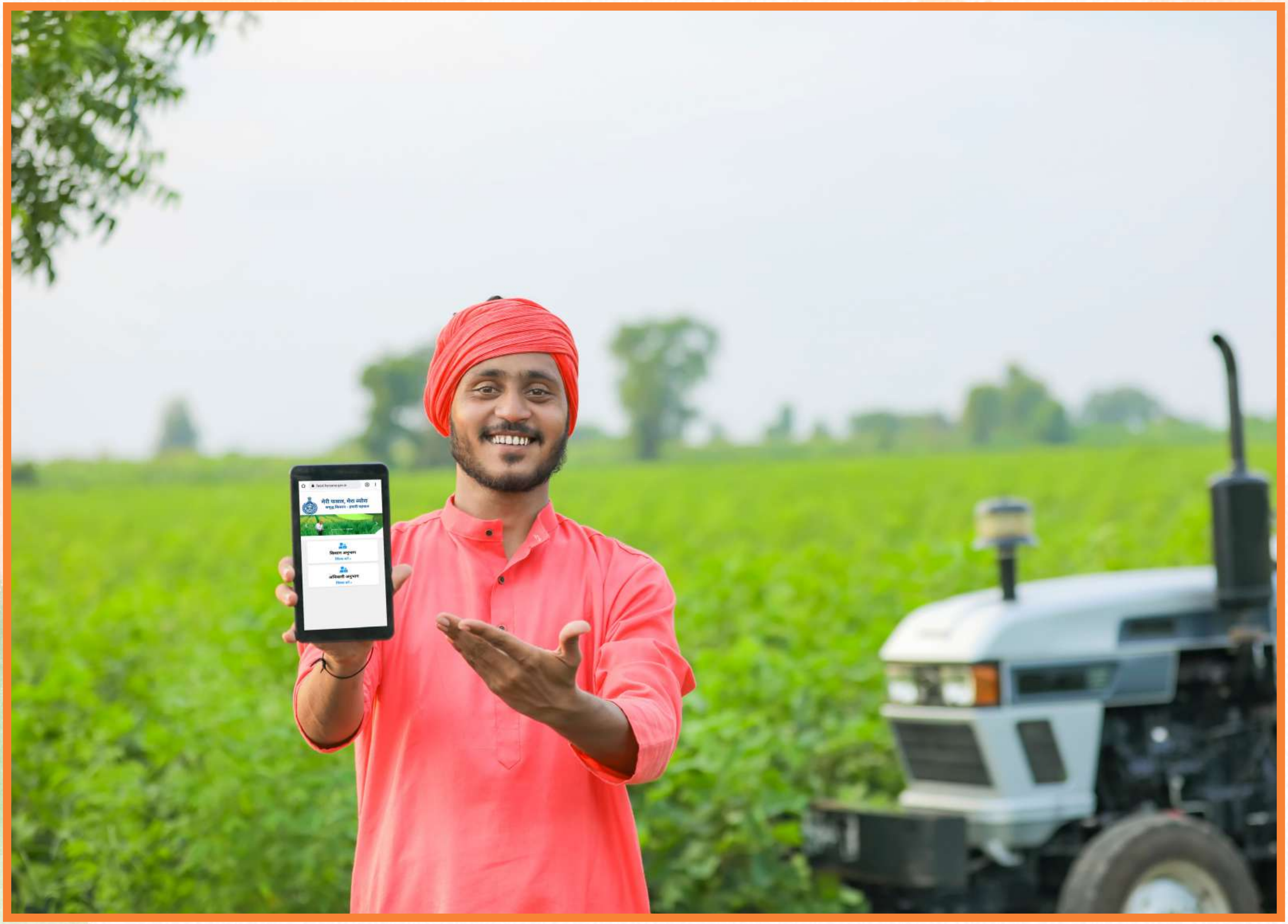

मेरी फसल, मेरा ब्योरा
किसान अनुभाग
अधिकारी अनुभाग

मेरी फसल–मेरा ब्यौरा

1. पहचान की गई समस्या

- मौजूदा गिरदावरी में किसानों द्वारा बोई गई फसल के आंकड़ों में विश्वसनीयता की कमी होना।
- बोई गई फसलों के दस्तावेज बनाने में किसानों का शामिल न होना।
- पटवारियों द्वारा गिरदावरी के इंदराज पर किसानों का मतभेद होना।
- खरीद प्रक्रिया के साथ भूमि रिकॉर्ड का न जुड़ना।
- किसानों से संबंधित सभी लाभकारी योजनाएं अलग–अलग संचालित होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है।
- किसानों को हर योजना के लिए बार–बार भू–रिकॉर्ड निकलवाना पड़ता था।
- किसानों को उनकी फसल की उपज के भुगतान में देरी होना।
- किसान खरीद और भुगतान के लिए कमीशन एजेंटों (आढ़तियों) की दया पर निर्भर थे।
- खरीद शुरू होने से पहले क्षेत्रवार और गांववार खरीद के लिए संभावित फसल पर विश्वसनीय डेटा का उपलब्ध न होना।

2. राज्य द्वारा किए गए सुधार

- राज्य द्वारा स्वयं एक ऐसा आई.टी. प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, जिस पर किसान स्वयं अपनी जमीन के प्रत्येक टुकड़े पर बोई गई फसल की जानकारी दर्ज करता है।
- इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है।
- परिवार पहचान पत्र में आंकड़ों के आधार पर ओ.टी.पी. आधारित प्रमाणीकरण किया जाता है।
- किसान द्वारा भूमि, फसल, फसल की किस्म, खरीद के तरीके का विवरण पंजीकृत किया जाता है।
- आगे की खरीद के लिए किसानवार, क्षेत्रवार, मंडीवार और फसलवार अनुमानित उत्पादन ई–खरीद आई.टी. प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
- मंडी में फसल लाने का समय निर्धारण किसान द्वारा किया जाता है।
- किसान खरीद और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- सभी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज होती हैं।
- डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के साथ सीधा जोड़ना।
- किसान को कोई भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- किसान अपना बैंक विवरण प्रदान करेगा, जिसमें उसका असली नाम होगा ताकि भुगतान केवल पंजीकृत किसान के खाते में ही किया जा सके।
- किसान द्वारा भरे गए फसल आंकड़ों की प्रमाणिकता 3 अलग–अलग तरीकों से होगी–
  - ❖ क्षेत्र स्तर के डेटा की उपग्रह इमेजिंग द्वारा।
  - ❖ पटवारी द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज गिरदावरी द्वारा।
  - ❖ कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भरे गए प्रत्येक क्षेत्र के लिए फसल आंकड़े द्वारा।
- उपग्रह इमेजिंग के लिए फसल हस्ताक्षर निर्देशिका तैयार करना।
- विभिन्न 4 स्तरों पर एकत्रित आंकड़ों में एकरूपता न होने पर इस आंकड़े को डी.सी., ए.डी.सी., एस.डी.एम. और अन्य एच.सी.एस. अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापित किया जाता है।
- सभी खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस करने के लिए खरीद प्रक्रिया को इससे जोड़ना।
- सत्यापित किसानों के खाते में निर्धारित समय में सीधे भुगतान सुनिश्चित करना।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा
फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू
https://fasal.haryana.gov.in
फसल पंजीकरण करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज :
1. आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र
2. मोबाईल नंबर
3. जमीन की जानकारी
(मुरब्बा नंबर, खसरा नंबर)
4. बैंक की पासबुक की कॉपी
पोर्टल पर अपनी फसल का सही पंजीकरण करवाए और पाए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ

- किसी भी फसल की खरीद को आसान बनाना।
- बीज उत्पादन, पराली प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई जैसी कई कृषि योजनाओं और फसल खराब होने पर गलत मुआवजा क्लेम करने पर रोक लगाने के लिए मेरी फसल–मेरा ब्यौरा आंकड़ों के साथ जोड़ना।

3. लाभ

- खरीदी गई फसल का किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित।
- सरकार खरीद के भुगतान में 72 घंटे से अधिक की देरी पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करती है।
- खरीद में गड़बड़ी पर नियंत्रण।
- MSP पर 14 फसलों की सरकारी खरीद।

4. परिणाम

- पंजीकृत किसानों की कुल संख्या– 9.25 लाख।
- रबी–2021 में 62 लाख एकड़, खरीफ–2021 में 52 लाख एकड़ क्षेत्र पंजीकृत।
- भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से पिछले दो साल में हरियाणा में धान की खरीद में 15 प्रतिशत की कमी आई।
- पिछले तीन खरीद सीजनों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का DBT द्वारा भुगतान।
- बाजरे की 'भावांतर भरपाई' के रूप में 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 429 करोड़ रुपये, 2 लाख 38 हजार 245 किसानों के खातों में सीधे डाले।

लाभार्थी

मैं पिछले तीन वर्षों से मेरी फसल–मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करवा रहा हूँ और MSP पर अपनी फसल को बेच रहा हूँ। MSP पर बेची फसलों से मेरी आय में वृद्धि हुई है, जिसके माध्यम से मैंने अपना मकान बनवाया है। मेरी फसल–मेरा ब्यौरा ने भ्रष्टाचार कम किया है और आय में वृद्धि की है।

(मोहन लाल मेहता, कुलताजपुर, महेंद्रगढ़)

मैं 12 एकड़ की खेती करता हूँ जिसमें से खरीफ–2021 में मैंने 5 एकड़ में नरमा व 7 एकड़ में धान की फसल लगाई थी। मैं हर वर्ष खरीफ व रबी सीजन में मेरी फसल–मेरा ब्यौरा के अंतर्गत पंजीकरण करवाता हूँ जिस कारण मुझे मंडी में फसल बेचने व बेची गई फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं आती। इसके अतिरिक्त विभाग की किसी भी अन्य योजना जैसे– मेरा पानी–मेरी विरासत, पराली प्रबंधन इत्यादि में भी पंजीकरण नंबर काफी सहायक होता है।

(महावीर प्रसाद, केलनिया, सिरसा)

विराम चिह्न
Punctuation marks

ऑनलाइन स्थानांतरण नीति

1. पहचान की गई समस्या

- पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में स्थानांतरण एक उद्योग बन गया था। वर्षभर स्थानांतरण चलते रहते थे।
- स्थानांतरण में भ्रष्टाचार होता था।
- कहीं पर जरूरत से अधिक अध्यापकों का होना और कहीं अध्यापकों की कमी होना।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार

- वर्षभर चलने वाले इस स्थानांतरण उद्योग पर ताला जड़ने के लिए अध्यापकों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू की।
- ऐसे कॉडर में यह नीति लागू की थी, जिसमें 500 या उससे अधिक पद हैं।
- फिर उन कॉडर में भी यह नीति लागू करने का निर्णय लिया गया, जिनमें 300 या उससे अधिक पद हैं।
- अब यह नीति उन कॉडर में भी लागू कर दी है, जिनमें 80 या उससे अधिक पद हैं।

3. लाभ

- तबादला उद्योग पर ताला लगा।
- भ्रष्टाचार में कमी।
- शिक्षकों को मनपसंद स्टेशन मिलने से उनके काम की गुणवत्ता में सुधार।

4. परिणाम

- यह नीति 43 विभागों के 214 कॉडर में लागू, जिनमें से 74 कॉडर में अधिसूचित की जा चुकी है।
- इस नीति की उपयोगिता को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है।

SARAL COUNTER (SINGLE
काउंटर (एकल
WINDOW)
8
9

अंत्योदय सरल पोर्टल

1. पहचान की गई समस्या

- सभी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न होना।
- योजनाओं व सेवाओं के लाभ प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया।
- निर्धारित समय सीमा में योजनाओं व सेवाओं का लाभ न मिलना।
- जिला, उपमण्डल व तहसील स्तर पर पर्याप्त केंद्र उपलब्ध न होना।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा लाभ के लिए जिला, उपमण्डल व तहसील स्तर पर बार–बार चक्कर लगाने को मजबूर होना।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार

- सभी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी के लिए एक ही ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध।
- इसके लिए सरल पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व पेपरलैस तरीके से सुनिश्चित की गई।
- जिला, उपमण्डल व तहसील स्तर पर अत्याधुनिक प्रणाली से सेवाओं व योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 100 से अधिक केन्द्र संचालित।
- ग्रामीण स्तर पर अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से योजनाओं व सेवाओं के लाभ उपलब्ध कराना।
- अंत्योदय सरल के माध्यमः–

  (क) ऑनलाइन प्लेटफार्म, (ख) नागरिक सेवा केन्द्र
- सेवा प्रदायगी केन्द्रः–

  ❖ जिला मुख्यालयः अंत्योदय भवन (योजनाओं के लिए)

  ❖ जिला मुख्यालयः सरल केन्द्र (सेवाओं के लिए)

  ❖ उपमण्डलः अंत्योदय सरल केन्द्र (योजनाओं व सेवाओं के लिए)

  ❖ तहसील स्तरः अंत्योदय सरल केन्द्र (योजनाओं व सेवाओं के लिए)

3. लाभ

- लोगों को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही मंच पर।
- पंक्ति के अंतिम नागरिक को उसके घर–द्वार पर ही योजनाओं व सेवाओं की जानकारी तथा लाभ।
- योजनाओं व सेवाओं के लाभ के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति।
- नागरिकों को आराम – आसानी से काम

  ❖ टोकन–नागरिकों को लाइन में न लगना पड़े इसके लिए, 'पहले आएं–पहले पाएं' आधार पर टोकन की सुविधा।

  ❖ प्रतीक्षा कक्ष– नागरिकों के लिए वातानुकूलित कक्ष की सुविधा।

  ❖ प्रत्येक सेवा केन्द्र पर एक हेल्प डेस्क स्थापित।

  ❖ सेवा व योजना सम्बंधी प्रश्नों और शिकायतों के लिए एक राज्यव्यापी हेल्पलाइन नं. 0172–3968400 जारी।

4. परिणाम

- सरल पोर्टल पर 42 विभागों की 589 सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन।
- इस पोर्टल पर मासिक आधार पर 5.5 लाख से अधिक आवेदनों की प्राप्ति।
- अब तक 4 करोड़ 82 लाख 54 हजार आवेदन प्राप्त।
- आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित करने हेतु प्रतिमाह 20 लाख से अधिक एस.एम.एस. भेजे जाते हैं।
- कॉल सेंटर पर 1 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुईं।
- औसत नागरिक फीडबैक स्कोर 5 में से 4.3 से अधिक है।

SARAL KENDRA सरल केन्द्र
SARAL Helpline : 1800-2000-023
COUNTER NO. 1
DOCUMENT VERIFICATION COUNTER
दस्तावेज सत्यापन काउंटर
SARAL KENDRA
सरल केन्द्र

सरल केन्द्र गुरुग्राम
SARAL KENDRA GURUGRAM

अंत्योदय
सरल केन्द्र
सिरसा

वरिष्ठ नागरिक ई-सुविधा
SARAL COUNTER (SINGLE WINDOW)
सरल काउंटर (एकल विन्डो)
Help Desk for Sen. Citizen/Ladies
वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं के लिये

लाभार्थी

जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था तब मुझे सरल केंद्र की जानकारी हासिल हुई। पहले सरकारी काम करने का मतलब था पूरे दिन की बर्बादी और अफसरों के पीछे चक्कर लगाना। सरल केंद्र खुलने की वजह से सभी काम बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं और सरकार का सरल केंद्र खोलना बहुत ही सराहनीय कार्य है। राज्य की सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ इस एक ही सरल पोर्टल के माध्यम से उठा सकते हैं।

(पुनीत, ओल्ड फरीदाबाद)

मुझे सरल केंद्र की जानकारी ग्राम पंचायत से मिली, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और बहुत ही आसान तरीके से जन्म प्रमाण पत्र का कार्य हो गया। सरल केंद्र की जानकारी का बुजुर्गों को भी अब पता है। पहले सरकारी काम के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते थे और काफी समय भी बर्बाद होता था। लेकिन अब सरकार द्वारा शुरू किये गए सरल केंद्र की वजह से सरकारी काम भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं और समय पर कार्य भी पूरा हो जाता है। हरियाणा राज्य के किसान समेत हर नागरिक सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ सरल केंद्र से उठा सकता है।

(जय चंद, बादशाहपुर, फरीदाबाद)

लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी में टाईटल डीड़ का
परिवार समृद्धि योजना पोर्टल

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

1. पहचान की गई समस्या

- लाल डोरे के भीतर गांव में किसी प्रकार की संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड नहीं था।
- मकान या प्लॉट की खरीद व बिक्री के समय रजिस्ट्री नहीं होती थी।
- संपत्ति पर बैंक से ऋण भी नहीं मिलता था।
- मालिकाना हक पर भी झगड़े होते रहते थे।

2. राज्य द्वारा किये गये सुधार

- राज्य में गांवों की मैपिंग का काम शुरू किया।
- ग्रामीण और आबादी देह क्षेत्र का फील्ड वेरिफिकेशन का कार्य किया गया।
- लाल डोरे के भीतर की हर सम्पत्ति का मानचित्रण किया।
- प्रत्येक सम्पत्ति को विशिष्ट पहचान दी गई।

3. लाभ

- भू–मालिकों को मालिकाना हक मिला।
- जमीन की खरीद–फरोख्त व उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला।
- मालिकाना हक से सम्बन्धित विवादों पर अंकुश लगा।
- कोई भी व्यक्ति गली या पंचायत की अन्य जमीन को दबा नहीं पाएगा।
- नाममात्र के स्टाम्प शुल्क पर टाइटल डीड पंजीकृत किए जा रहे हैं।
- लाल डोरे के भीतर हर सम्पत्ति को परिवार पहचान–पत्र से जोड़ा।

4. परिणाम

- इस योजना के तहत अब तक कुल 6,309 गांव कवर किए गए।
- पात्र लाभार्थियों की संख्या 20 लाख है, जिनमें से 64 प्रतिशत यानि कि 12 लाख 77 हजार 807 लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है।
- कुल 12 लाख 77 हजार 807 संपत्ति कार्ड हैं, जिनमें से 3 लाख 66 हजार 682 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

लाभार्थी

मुझे अपने जमीन का मालिकाना हक मिलने से पहले हमेशा यह डर सताता रहता था कि कोई बाहुबली मेरी जमीन पर कब्जा न कर ले। जब सरकार ने खुद से पहल करके हमें हमारी जमीन का कानूनी हक दिलाया है, तो मुझे इस डर से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। अब न केवल मेरी जमीन को लेकर के किसी भी तरह के विवाद व झगड़े की संभावना खत्म हुई है बल्कि विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कृषि व अन्य लोन का लाभ लेने की पात्रता भी मिली है। इसके लिए मैं सरकार का दिल से आभारी हूँ।

(नज़ीर, गांव–पल्ला, नूंह)

महामना पंडित मदन
मालवीय जी
एवं
पूर्व प्रधानमंत्री
भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी
उपलक्ष्य में
दिवस
मुख्यमंत्री, हरियाणा
E-GRANTHKOSH
E-GRANTHKOSH
E-GRANTHKOSH

सुशासन से सेवा

- वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया और 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए 'सी.एम. विंडो पोर्टल' शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 8 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 18 लाख से अधिक किसानों को 3961 करोड़ रुपये बीमा क्लेम के रूप में दिए।
- भावांतर भरपाई योजना में शामिल सभी 21 बागवानी फसलों को 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' के तहत 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक बीमा कवर।
- संकट के समय तुरंत मदद प्रदान करने के लिए आई.टी. का उपयोग कर सभी आपातकालीन सेवाओं को मिलाकर 'हरियाणा–112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली' संचालित।
- सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डी.बी.टी. से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया।
- जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण–पत्र ऑनलाइन जारी करने शुरू किये।
- भूमि विवादों के निपटान में रिमांड एक बड़ी बाधा थी जो भ्रष्टाचार की जननी थी। रिमांड की प्रथा को खत्म किया।
- सी.एल.यू. को पूरी तरह ऑनलाइन किया।
- ई–पंजीकरण प्रणाली के तहत रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट।
- सरकारी कामकाज में तेजी लाने और फाइलों के शीघ्र निपटान के लिए 'ई–ऑफिस' की शुरुआत। इस पोर्टल से 50 से अधिक विभागों और सभी 22 उपायुक्त कार्यालयों के 26 हजार से अधिक उपयोगकर्त्ता व अधिकारी जुड़े हुए हैं। अब तक सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा 23 लाख से अधिक फाइलें और 19 लाख से अधिक प्राप्तियां स्थानांतरित की जा चुकी हैं।
- जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए WEB HALRIS पूरे प्रदेश में लागू।
- खनन ठेकों में ई–नीलामी और ई–रवाना स्कीम से पारदर्शिता।
- डिजिटल साधनों से सेवाओं व योजनाओं का लाभ देने के लिए अलग से 'नागरिक संसाधन सूचना विभाग' का गठन किया।
- आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम' बनाया।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित सभी विषयों के लिए मानव संसाधन विभाग गठित।
- व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई–वे बिल योजना।
- किसानों को फसलों की ऑनलाइन बिक्री सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य की 81 मंडियों को E-NAM पोर्टल से जोड़ा गया है।
- सुशासन और Service Delivery में टेक्नॉलाजी का भरपूर इस्तेमाल करने के साथ–साथ समाज के लिए कुछ कर–गुजरने का जज़्बा रखने वाले समर्पित स्वयंसेवकों का सहयोग लेने के उद्देश्य से स्वैच्छिक कार्यक्रम 'समर्पण' शुरू किया गया है।
- युवाओं को नौकरी के लिए बार–बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए 'एकल पंजीकरण' की सुविधा शुरू की गई है।

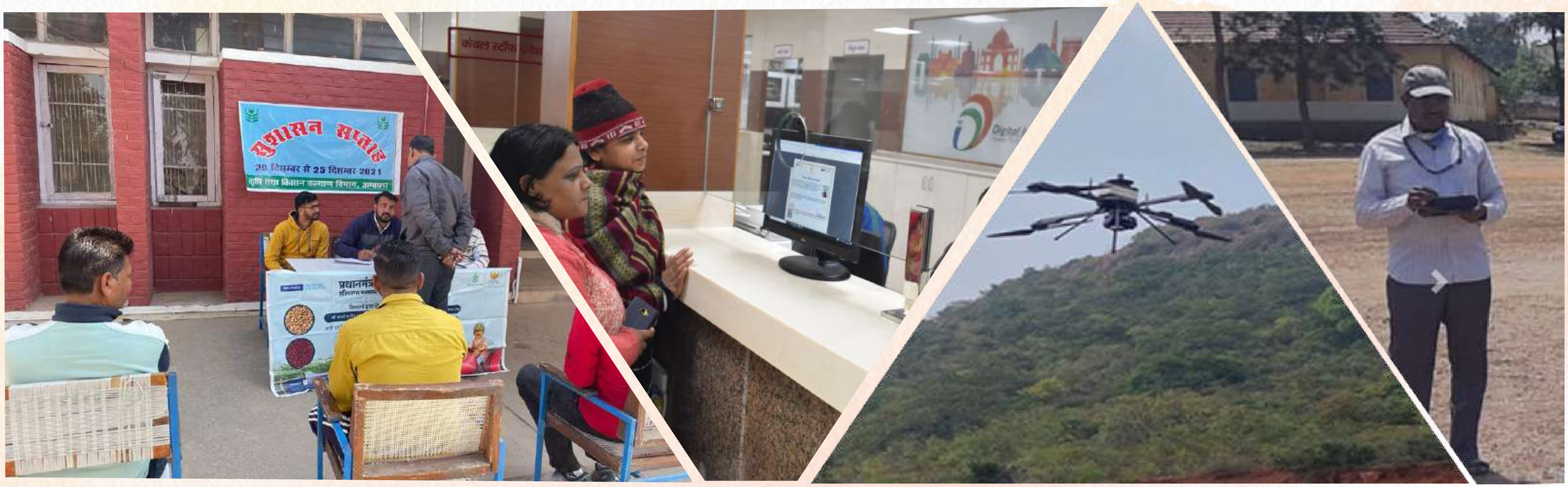
सुशासन सप्ताह
20 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2021

CM WINDOW
मुख्यमन्त्री समस्या निवारण पटल
आपकी समस्याओं का निदान
स्वागत हरियाणा
जिला मुख्यालय: करनाल

नकल जमाबन्दी

हरियाणा की नई पहलें, जो केंद्र व दूसरे राज्य की सरकारों के लिए बनी प्रेरणा

- गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' करने की योजना को केन्द्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना' के रूप में पूरे देश में लागू किया।
- 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया।
- कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर में गांव–गांव और घर–घर जाकर जांच अभियान चलाया, तो केन्द्र सरकार ने ऐसा अभियान हर प्रदेश में चलाने की बात कही।
- ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की उपयोगिता को देखते हुए कई दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है।
- प्रदेश की खेल नीति का मूल्यांकन करने के लिए गुजरात सरकार की एक टीम ने दौरा किया।
- प्रदेश में पढ़ी–लिखी पंचायतों की व्यवस्था की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सराहना की।

हरियाणा को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान

क्रमांक	पुरस्कार	वर्ष	विवरण
			वर्ष 2015
1.	इलेट्स नॉलेज एक्सचेंज अवार्ड्स	22 मई, 2015	समेकित मेडिको लीगल जांच और पोस्टमार्टम और फोरेंसिक साईंस लैबोरिट्रीज रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए।
2.	ग्रिड बायोमास गैर–बगै से आधारित संयंत्रों की सर्वोच्च अतिरिक्त क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार	29 अगस्त, 2015	बायोमास सह – उत्पादन बिजली परियोजनाओं से 18.90 मेगावॉट की सर्वोच्च अतिरिक्त क्षमता के लिए।
3.	नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों की स्थापना के लिए एस.एन.ए.ज. की हरित भवनों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार	29 अगस्त, 2015	पंचकूला में हरेडा की भावी ऊर्जा दक्षता और हरित कार्यालय भवन के लिए।
4.	स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड	22 सितम्बर, 2015	हरियाणा में व्यापक ई–शासन की पहल करने के लिए।
5.	स्कॉच "ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड"	22 सितम्बर, 2015	नवजात शिशुओं का जन्म के समय ही आधार पंजीकरण के लिए।
6.	स्कॉच "ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड"	22 सितम्बर, 2015	ई–टूरिजम पर्यटन सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग के लिए।
7.	स्कॉच "ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड"	22 सितम्बर, 2015	समेकित वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के उचित क्रियान्वयन के लिए।
8.	स्कॉच "ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड"	22 सितम्बर, 2015	ई–जिला/ई–दिशा के लिए।
9.	स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड	23 सितम्बर, 2015	ई–जिला/ई–दिशा के लिए।
10.	स्कॉच "ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड"	22 सितम्बर, 2015	जीवन प्रमाण–पत्र के साथ आधार सक्षम ई–पेंशन एकीकरण के लिए।
11.	स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड	23 सितम्बर, 2015	जीवन प्रमाण–पत्र के साथ आधार सक्षम ई–पेंशन एकीकरण के लिए।
12.	स्कॉच "ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड"	22 सितम्बर, 2015	जन शिकायत निवारण के लिए सी.एम. विंडो के लिए।
13.	स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड	23 सितम्बर, 2015	जन शिकायत निवारण के लिए सी.एम. विंडो के लिए।
14.	**अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस**	3 दिसम्बर, 2015	सी.एस.आई.के. 50वें गोल्डन जुबली सम्मेलन में पूरे प्रदेश में ई–शासन प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए।
15.	**अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस**	3 दिसम्बर, 2015	सी.एस.आई.के. 50वें गोल्डन जुबली सम्मेलन में सी.एस.आई.–निहीलेंट की परियोजना श्रेणी।
16.	थ्री डिजिटल इंडिया अवार्ड	28 दिसम्बर, 2015	पंचकूला, जींद और सिरसा जिलों में डिजिटल इंडिया वीक की पहलों को सुशासन दिवस पर सम्मान प्रदान किया गया।
17.	**कृषि कर्मण पुरस्कार**	वर्ष 2015	चावल की फसल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रदान किया गया।
18.	अन्य वसूली क्षेत्र में तकनीकी दक्षता	वर्ष 2015	अन्य वसूली क्षेत्र में वर्ष 2015–16 के लिए तकनीकी दक्षता के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल को प्रथम पुरस्कार।
19.	गन्ना विकास के लिए	वर्ष 2015	वर्ष 2015–16 गन्ना विकास के लिए करनाल सहकारी चीनी मिल को द्वितीय पुरस्कार।
			वर्ष 2016
20.	सर्वोच्च सहकारी गन्ना मिल के लिए	वर्ष 2016	सर्वोच्च सहकारी गन्ना मिल में वर्ष 2016–17 के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल को पुरस्कार।
21.	गन्ना विकास के लिए	वर्ष 2016	वर्ष 2016–17 में गन्ना विकास के लिए करनाल सहकारी चीनी मिल को प्रथम पुरस्कार।

22.	गन्ना विकास के लिए	वर्ष 2016	वर्ष 2016–17 में गन्ना विकास के लिए पानीपत सहकारी चीनी मिल को द्वितीय पुरस्कार।
23.	तकनीकी दक्षता के लिए	वर्ष 2016	वर्ष 2016–17 के लिए तकनीकी दक्षता के लिए कैथल सहकारी चीनी मिल को द्वितीय पुरस्कार।
24.	**फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया**	27 फरवरी, 2016	नवजात शिशुओं के जन्म पंजीकरण को आधार से जोड़ने के लिए।
25.	**नारी शक्ति अवार्ड**	8 मार्च, 2016	शिशु लिंगानुपात सुधार में प्रगति कार्य के लिए।
26.	**राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित सौर प्रौद्योगिकी तथा सौर कुकर उत्कृष्टता पुरस्कार**	29 अप्रैल, 2016	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों से सौलर कुकर को प्रोत्साहित करने के लिए।
27.	**सामान्य श्रेणी के राज्यों में सौर ऊर्जा रूफटॉप बिजली परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार**	7 जून, 2016	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य को रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए।
28.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	8 सितम्बर, 2016	एस.आर.डी.बी. (स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस) अपने सभी निवासियों के लिए एक राज्य–एक दृष्टिकोण की स्थापना।
29.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	8 सितम्बर, 2016	म्हारी पंचायत–नागरिकों और पी.आर.आई. का सशक्तिकरण।
30.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	8 सितम्बर, 2016	सी.ई.एफ.एम.ए.टी.आई.एस. (केन्द्रित फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सिस्टम)।
31.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	8 सितम्बर, 2016	ए.ई.बी.ए.एस. (आधार सक्षम बायोमैट्रिक एटेडेंस सिस्टम)।
32.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	8 सितम्बर, 2016	औषध खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन – डीपीएमयू।
33.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	8 सितम्बर, 2016	ई–टी.डी.एस. (संसाधन पर ई–टैक्स कटौती)।
34.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	8 सितम्बर, 2016	ई–ग्रास (सरकारी प्राप्तियां स्वीकार प्रणाली)।
35.	स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड	9 सितम्बर, 2016	वाणिज्यिक कर एम.पी.पी. (डीलर्स प्रबन्धन के लिए ई–एप्लीकेशन, रिर्टनस की ई–फाईलिंग, सी–फार्म इत्यादि)।
36.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2016	वाणिज्यिक कर एम.पी.पी. (डीलर्स प्रबन्धन के लिए ई–एप्लीकेशन, रिर्टनस की ई–फाईलिंग, सी–फार्म इत्यादि)।
37.	**स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड**	9 सितम्बर, 2016	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ई.आर.पी. प्रणाली–समेकित कार्य निगरानी, वस्तु सूची, सरकारी लेखा प्रणाली और बी.आई.एस.डब्ल्यू.ए.एस.।
38.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2016	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ई.आर.पी. प्रणाली–समेकित कार्य निगरानी, वस्तु सूची, सरकारी लेखा प्रणाली और बी.आई.एस.डब्ल्यू.ए.एस.।
39.	**स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्डस**	9 सितम्बर, 2016	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की परियोजना डी.बी.टी. थारी पेंशन–थारे पास के माध्यम से हरियाणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
40.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2016	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की परियोजना डी.बी.टी. थारी पेंशन–थारे पास के माध्यम से हरियाणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
41.	"Best Horticulture State Award"	9 सितम्बर, 2016	बागवानी क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के लिए प्रदेश को 'Best Horticulture State Award' दिया गया।
42.	**इंडिया टूडे प्रेसटीजियेश अवार्ड**	5 नवम्बर, 2016	पिछले दो वर्षों के दौरान ई–शासन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ई–शासन श्रेष्ठ उन्नत राज्य।
43.	**निहीलेंट अवार्ड**	9 दिसम्बर, 2016	सामाजिक सुरक्षा पेशन डी.बी.टी. के माध्यम से ।
44.	वेब रतना स्टेट सिल्वर	19 दिसम्बर, 2016	डिजिटल इंडिया।
45.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2016	ई–रजिस्ट्रेशन के लिए।

वर्ष 2017			
46.	तकनीकी दक्षता के लिए	वर्ष 2017	तकनीकी दक्षता में वर्ष 2017–18 के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल को प्रथम पुरस्कार।
47.	गन्ना विकास के लिए	वर्ष 2017	वर्ष 2017–18 में गन्ना विकास के लिए करनाल सहकारी चीनी मिल को प्रथम पुरस्कार।
48.	**नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड– गोल्ड**	9 जनवरी, 2017	नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड– गोल्ड ई–शासन में जी.आई.एस. टैक्नोलोजी के अनूठे उपयोग के लिए जिला प्रशासन गुरुग्राम की जी–त्रिकोणीय परियोजना के लिए प्रदान किया गया।
49.	**डिजिटल इंडिया अवार्ड**	19 जनवरी, 2017	कैशलेस लेन–देन की पहल के लिए।
50.	सी.एस.आई. निहीलेंट अवार्ड ऑफ एपप्रीसीऐशन	20 जनवरी, 2017	कर्मचारियों के ऋण प्रबंधन प्रणाली के लिए।
51.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	20 जनवरी, 2017	औषध खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन प्रणाली के लिए।
52.	सी.एस.आई. निहीलेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस	24 जनवरी, 2017	ई–स्टैम्पिंग के साथ ई–ग्रास का एकीकरण।
53.	सी.एस.आई. निहीलेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस	24 जनवरी, 2017	ई–डिस्ट्रिक्ट हरियाणा।
54.	**बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ**	24 जनवरी, 2017,	जिला यमुनानगर को कन्या शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए।
55.	**प्रशंसा पुरस्कार**	24 जनवरी, 2017	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की डी.बी.टी. परियोजना।
56.	**स्वच्छता सर्वेक्षण 2017**	मई, 2017	स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में करनाल शहर उत्तरी भारत में दो से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में पहले स्थान पर चुना गया।
57.	जेम ऑफ डिजिटल इंडिया	7 जून, 2017	संपत्ति पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड तथा कैडस्ट्राल मानचित्रों का गतिशील एकीकरण करने के लिए।
58.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की परियोजना डी.बी.टी. थारी पेंशन–थारे पास के माध्यम से हरियाणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
59.	स्कॉच गोल्ड अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	ई–लर्निंग कलासिज प्रोजेक्ट के लिए।
60.	स्कॉच गोल्ड अवार्ड	2017	ई–समर्थ एन.आई.सी. कुरुक्षेत्र।
61.	स्कॉच गोल्ड अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	एन.आई.सी. हिसार को मतदान प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए।
62.	स्कॉच गोल्ड अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणाओं की उचित निगरानी के लिए।
63.	स्कॉच सिल्वर अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	सी.एम. ई–डैशबोर्ड के लिए।
64.	स्कॉच सिल्वर अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	वास्तविक समय स्वचालित प्रतिक्रिया डैशबोर्ड के लिए।
65.	स्कॉच सिल्वर अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए।
66.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	सरकारी रसीद लेखा प्रणाली के लिए।
67.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	मेडिको–लीगल परीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए।
68.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	औषध खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन–डी.पी.एम.यू.।
69.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	राजस्व कोर्ट केसों की निगरानी के लिए।
70.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा परीक्षा के लिए।
71.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	करनाल जिले को जमाबंदियों की तैयारी और प्रेषण के लिए।
72.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	राज्य सुरक्षा की सूचना प्रबंधन के लिए।

73.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में राजस्व और पूंजी के रूप में बजट का पुनः निर्धारण के लिए।
74.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	सामान्य वितरण प्रणाली को आधार से जोड़ने के लिए।
75.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	ई–गिरदावरी के लिए।
76.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	ई–जिला/ई–दिशा के लिए।
77.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	कृषि से सम्बन्धित लाइसेंस जारी करने की प्रणाली के लिए।
78.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	ई–स्टैम्पिंग प्रणाली के लिए।
79.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	ऑनलाइन ट्रेजरी सूचना प्रणाली के लिए।
80.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	कोषागार तथा लेखा विभाग के आभासी भुगतान के लिए।
81.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	एकीकृत वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए।
82.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	एकीकृत ऑनलाइन नगरपालिका प्रणाली के लिए।
83.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	आगंतुक पास प्रबंधन प्रणाली के लिए।
84.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं को ऑनलाइन करने के लिए।
85.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	9 सितम्बर, 2017	वाहनों के पंजीकरण, कर, परमिट जैसी केंद्रीय सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए।
86.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	2017	सी.एम. विंडो के लिए।
87.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	2017	आधार लिंक भूमि रिकॉर्ड सिस्टम के लिए।
88.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	2017	आधार लिंक बायोमेट्रिक अंटेन्डंस सिस्टम के लिए।
89.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	2017	रक्षा विभाग के पेंशनर के आधार लिंक जीवन प्रमाण–पत्र के लिए।
90.	"चैंपियन ऑफ चेंज" अवार्ड	9 नवम्बर, 2017	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार अधिकतम शिक्षु लगाने की उपलब्धि के लिए।
91.	इडिया टूडे स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड	16 नवम्बर, 2017	समावेशी विकास और पर्यटन विकास के क्षेत्र में ।
92.	स्कॉच "ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड"	20 दिसम्बर, 2017	तकनीकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए।
93.	स्कॉच "प्लेटिनम अवार्ड"	21 दिसम्बर, 2017	तकनीकी परियोजनाओं के विकास के लिए।
			वर्ष 2018
94.	**ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस**	वर्ष 2018	उद्योगों से सम्बन्धित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए।
95.	**Power Award**	3 जनवरी, 2018	For optimum and efficient utilization of water resources.
96.	निहीलेंट अवार्ड	जनवरी, 2018	औषध पोर्टल के लिए।
97.	**गोल्ड अवार्ड**	2018	मोबाइल एप जियो ओ.डी.एफ.।
98.	निहीलेंट अवार्ड	2018	कर्मचारी ऋण प्रबंधन सिस्टम।
99.	निहीलेंट अवार्ड	2018	ऑनलाइन औषध खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन।
100.	निहीलेंट अवार्ड	2018	ई–परिवहन एम.एम.पी. कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के लिए।
101	निहीलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड	2018	अंत्योदय सरल के लिए।

102.	**बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ**	8 मार्च, 2018	जिला सोनीपत को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की तीसरी वर्षगांठ पर पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट को सही ढ़ग से लागू करने के लिए।
103.	स्कॉच ''ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड''	23 जून, 2018	सही समय पर फसलों को आग लगाने की तुरंत चेतावनी देने के लिए।
104.	स्कॉच ''ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड''	23 जून, 2018	संपत्ति मान चित्रण एप्लीकेशन।
105.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	23 जून, 2018	साईबर सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए।
106.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	23 जून, 2018	कैशलेस समेकन पोर्टल के लिए।
107.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	23 जून, 2018	कागज रहित डिजिटल लॉकर प्रणाली के लिए।
108.	जेम ऑफ डिजिटल इंडिया	जून, 2018	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लिए।
109.	जेम ऑफ डिजिटल इंडिया	जून, 2018	सड़क परिवहन के लिए।
110.	जेम ऑफ डिजिटल इंडिया	2018	सी.ई.एफ.एम.ए.टी.आई.एस. (केन्द्रित फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सिस्टम)
111.	बी.एफ.एस.आई. एक्सीलेंस अवार्ड	12 अगस्त, 2018	कैशलेस समेकन पोर्टल के लिए।
112.	बी.एफ.एस.आई. एक्सीलेंस अवार्ड	12 अगस्त, 2018	वास्तविक समय स्वचालित प्रतिक्रिया डैशबोर्ड के लिए।
113.	बी.एफ.एस.आई. एक्सीलेंस अवार्ड	12 अगस्त, 2018	विभागों की सेवाओं को आधार से जोड़ने के लिए।
114.	डिजिटल इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड	30 अगस्त, 2018	साईबर सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए।
115.	डिजिटल इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड	30 अगस्त, 2018	कागज रहित डिजिटल लॉकर प्रणाली के लिए।
116.	**स्वस्थ जननी–सुरक्षित शिशु**	7 सितम्बर, 2018	राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उत्तरी भारत क्षेत्र में पंचकूला व यमुनानगर जिलों की बेहतरीन उपलब्धि के लिये।
117.	**स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण–2018**	2 अक्तूबर, 2018	स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण–2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का अवार्ड जीता। स्वच्छता क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले देश के 6 जिलों में हरियाणा के 3 जिले (गुरुग्राम, करनाल, रेवाड़ी) शामिल।
118.	ई–इंडिया अवार्ड	13 दिसम्बर, 2018	साईबर सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए।
119.	ई–इंडिया अवार्ड	13 दिसम्बर, 2018	कैशलेस समेकन पोर्टल के लिए।
120.	**कानूनी सेवा प्राधिकरण**	17 दिसम्बर, 2018	केंद्रीय कानून व न्याय मंत्रालय द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 को हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।
121.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	22 दिसम्बर, 2018	साईबर सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए।
122.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	22 दिसम्बर, 2018	साईबर सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क के लिए।
123.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	22 दिसम्बर, 2018	हरियाणा राज्य आवेदन सुरक्षा लेखा–परीक्षा नीति के लिए।
124.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	22 दिसम्बर, 2018	कैशलेस समेकन पोर्टल के लिए।
125.	स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड	22 दिसम्बर, 2018	शिक्षुता अधिनियम, 1961 को लागू करने के लिए।
		वर्ष 2019	
126.	बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ	26 जनवरी, 2019	हरियाणा राज्य को सर्वांगीण सहायता, मार्गदर्शन, मोनीटरिंग श्रेणी के तहत।
127.	बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ	26 जनवरी, 2019	करनाल जिले को इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमैंट के लिए।

128.	बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ	26 जनवरी, 2019	झज्जर को एनेबलिंग गर्ल चाईल्ड एजूकेशन।
129.	बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ	26 जनवरी, 2019	कुरुक्षेत्र को पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट को सही ढंग से लागू करने के लिए।
130.	जेम ऑफ डिजिटल इंडिया	2019	ई–पंचायत प्रोजेक्ट।
131.	**गोल्ड अवार्ड**	21 फरवरी, 2019	डिजिटल इन्हानसमेंट प्लेटफार्म।
132.	वेब रतना स्टेट–प्लेटिनम	22 फरवरी, 2019	जिला प्रशासन, कुरुक्षेत्र की वेबसाइट के लिए।
133.	बिजनेस वर्ल्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड	28 जून, 2019	वेब हेलरिस।
134.	निहीलेंट अवार्ड	2019	सरल हरियाणा।
135.	**गोल्ड अवार्ड**	2019	डिजीटल इन्हानसमेंट प्लेटफार्म, जींद।
136.	**गोल्ड अवार्ड**	2019	वेब सर्विस पोर्टल के लिए एन.आई.सी., हिसार।
137.	सिल्वर अवार्ड	2019	प्रोजेक्ट रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सबट्रैक के तहत एन.आई.सी., कैथल।
138.	**गोल्ड अवार्ड**	2019	अन्त्योदय सरल केन्द्रों के माध्यम से ई–शासन में बेहतर कार्य करने के लिए।
139.	**कृषि कर्मण पुरस्कार**	2019	सरसों उत्पादन के लिए।
140.	**स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2019 में उत्तरी क्षेत्र में प्रदेश को प्रथम पुरस्कार**	2019	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए।
141.	**वैश्विक कृषि पुरस्कार–2019 में 'सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार'**	2019	पशुपालन क्षेत्र और किसान की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली नीतिगत पहलों के लिए।
142.	एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट–2018 में प्रथम पुरस्कार	2019	बिजली उत्पादन, वितरण व प्रसारण में लागत प्रबन्धन के लिए।
143.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तीसरा पुरस्कार	2019	योजना को राज्य में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए।
144.	राष्ट्रीय पुरस्कार	2019	दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम वेबसाइट बनाने के लिए।
			वर्ष 2020
145.	तकनीकी दक्षता के लिए	वर्ष 2020	पिराई सीजन 2019–20 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की दो सहकारी चीनी मिलों, करनाल सहकारी चीनी मिल ने गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार तथा कैथल सहकारी चीनी मिल ने तकनीक की दक्षता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए।
146.	स्कॉच गोल्ड अवार्ड	29 अक्तूबर, 2020	कोविड–19 के दौरान बेहतर प्रबंधन के लिए।
			वर्ष 2021
147.	डिजिटल इंडिया अवार्ड, 2020	2021	सरल पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध और बाधा मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए।
148.	**गोल्ड अवार्ड**	2021	अंत्योदय सरल परियोजना के लिए ।
149.	**स्टेट अवार्ड**	दिसम्बर 2021	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत।

जिलों की
सरल पोर्टल
की अतिरिक्त सेवाएं
डोरा मुक्त
91 तहसीलों के
वेब हैलरिस
NIC
National Informatics Centre
Digital Haryana
सुशासन
दिवस
के अवसर पर
श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार
द्वारा
लोकायुक्त पोर्टल
91 तहसीलों के